International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 01(II), January - March, 2023, pp. 127-129

जल ग्रहण विकास कार्यक्रम के उद्देश्य

डॉ. ललतेश जॉगिड़*
श्री रमेश चन्द कुमावत**

प्रस्तावना

विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में भूमि जल एवं वन का बेहतर तथा उपयुक्त प्रबंध वर्तमान क्षेत्रीय पर्यावरणीय दशाओ के लिए एक बाध्यता बन चुका है । इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने श्री हनुमंथ राव कमेटी का गठन करते हुए सभी क्षेत्र विशेष कार्यक्रम को एकीकृत करते हुए जल ग्रहण विकास कार्यक्रम की योजनाए तैयार की ।

जिसके प्रबंधन का उद्देश्य मिटटी और क्षेत्रीय उपलब्ध जल स्त्रोतों को क्षेत्रीय विकास हेतु अनुकूलतम /कुशल उपयोग करना है । जल ग्रहण विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते हुए निम्न उद्देश्य / उपलब्धियां प्राप्त करते हुए (क्षेत्रीय भौतिक परिस्थितियों के अनुकूल) क्षेत्रीय विकास की योजनाए तैयार करना होता है ।

भू संरक्षण कार्यक्रमों को बढावा देना

- मृदा संरक्षण एवं नमी संरक्षण द्वारा पर्यावरण अवनयन पर नियंत्रण।
- क्षेत्रीय भूमि क्षमता अनुसार भूमि उपयोग को आधुनिक तकनीकीयों के माध्यम से बढावा देना।
- अति चारण प्रक्रिया द्वारा मृदा अपरदन पर नियंत्रण करना।
- भू एवं जल संसाधनों का संतुलित विकास।
- आधुनिक तकनीक से फसलो की गहनता को बढ़ावा देना।
- मृदा अपरदन पर रोक लगाने हेतु वानस्पतिक अवरोध या अन्य विधियों को अपनाना।

जल संरक्षण विधियों को बढ़ावा देना

- वर्षा जल को संरक्षित करते हुए जल का वैज्ञानिक विधियों से सदुपयोग करना।
- भूमि जल स्तर के पुनर्भरण की विभिन्न विधियों को अपनाते हुए पुनर्भरण में वृद्धि करना।
- सुविधाजनक स्थिति तथा स्थानों पर वर्षा जल को संग्रहीत करना।
- शुष्क कृषि विधियों को बढ़ावा देना , तथा बाढ़ एवं सूखे की स्थिति के पुनरावृत्ति के उपायों को अपनाना ।

पारिस्थितिकी संतुलन को पुनःस्थापित करना

- क्षेत्रीय उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित सतत विकास एवं बायोमॉस को बढ़ावा देना
- ग्रामीण समुदायों की आवश्यकतानुसार भोजन चारा, ईधन की लकड़ी की उपलब्धता बढ़ाना।
- क्षेत्रीय भौगोलिक दशाओ के अनुकूल वृक्षारोपण को बढ़ावा देना
- वन्य जीवो के संरक्षण को बढ़ावा देना।

* सहायक आचार्य, भूगोल, मतस्य महाविद्यालय, बानसूर, अलवर, राजस्थान।
** सहायक आचार्य, भूगोल, मतस्य महाविद्यालय, बानसूर, अलवर, राजस्थान।

पशुपालन विकास

- पशुपालन क्रियाओ के तहत नस्ल सुधार कार्यक्रम को अपनाना।
- क्षेत्रीय मांग के अनुसार ऊन, दूध आदि के उत्पादन में आत्मनिर्भर होना।
- मत्स्य पालन को बढ़ावा देना।
- पशु स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओ का लाभ उठाना।

आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में सुधार

- क्षेत्रीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का विकास करते हुए जीवन स्तर में सुधार करना।
- गरीब एवं भूमिहीन मजदूरों / कृषको को कुटीर उद्योग, लघु उद्योग आदि के विकास के साथ ही तकनीकी प्रशिक्षण देना तथा रोजगार अवसरों को बढ़ावा देना।
- कृषि प्रणाली को उन्नत करना।
- सभी क्षेत्रीय विकासात्मक कार्यों में जन सहभागिता को बढ़ावा देना।

अतः उपरोक्त उद्देश्य के प्राप्ति के साथ ही किसी भी जलसंग्रहण क्षेत्र का विकास किया जा सकता है जिसमे सरकारी योजनाओ का सहयोग व सदुपयोग करते हुए जनसहभागिता के साथ क्षेत्र विशेष का संतुलित एवं सतत विकास प्रक्रिया अपनाई जा सकती है ।भूमि एवं जल, जलग्रहण क्षेत्र के प्राथमिक संसाधन है । इन दोनों के मध्य एक गहन हिस्सा है। इन दोनों के बीच होने वाली क्रियाएं एक दूसरे की किस्म एवं उपलब्धता को प्रभावित करती है । ये दोनों संसाधन जल ग्रहण क्षेत्र के भू उपयोग को निर्धारित करते है । भू उपयोग के साथ ही क्षेत्रीय आर्थिक विकास की योजनाए तैयार की जा सकती है । भू उपयोग ही उक्त संसाधनों के साथ स्थानीय मानव समुदाय के जीवन स्तर को प्रभावित करता है भूमि एवं जल के साथ –2 क्षेत्रीय जलवायु अपने आप में एक संसाधन माना गया है । और वह अन्य क्षेत्रीय घटकों के साथ साथ मानव की सभी गतिविधियों के साथ साथ मानव की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है । मृदा, जल एवं जलवायु के आपसी संबंधो एवं प्रक्रियाओ के आधार पर वनस्पति एवं जीव जन्तुओ का विकास होता है ।

इनके साथ –2 मानव सहभागिता एवं तकनीकी ज्ञान भी जलग्रहण विकास प्रक्रिया के स्तम्भ माने जाते है । जिनके मध्य भी सामंजस्य होना आवश्यक है । कई बार क्षेत्रीय विकास कार्यों में संलग्न संस्थाए उक्त पहलुओ पर ध्यान नहीं दे पाती है । किसी भी क्षेत्र में लागू की जाने वाली विकास योजनाओ का क्रियान्वन स्थानीय लोगो को विश्वास में लेकर ही किया जा सकता है । तथा उन्हें प्रस्तुत योजना एवं संसाधनों के प्रति जागरूक बनाना चाहिए । साथ ही उन्हें कृषि, बागवानी, जल प्रबन्धन, पशुपालन एवं वानिकी में सक्षम बनाया जाना आवश्यक है । इसके साथ ही कोई भी क्षेत्रीय योजना सही ओर उपयोगी सूचना तकनीकी के बिना नहीं बनायी जा सकती है ।

यह भी आवश्यक है कि किसी भी क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक एवं पर्यावरणीय विकास योजना क्रियान्वन से पूर्व उस क्षेत्र के सभी भौतिक एवं सांस्कृतिक, सामाजिक पक्ष का गहन अध्ययन एवं सामंजस्य आवश्यक है इन सभी पक्षों के आधार पर वहां का विस्तृत विकास प्रारूप (क्मजंपस क्मअमसवचउमदज च्तवपिसम) तैयार किया जा सकता है यह विकास प्रारूप क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली (छंजनतंस त्मेवनतबमे कंजं डंदंहमउमदज ैलेजमउ) के द्वारा तैयार किये जा सकते है । जिसके सम्बंधित क्षेत्र की उपयुक्त भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि सूचनाए सूक्ष्म स्तर पर प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको के द्वारा एकत्रित कर पोषणीय विकास हेतु विकास प्रारूप तैयार किया जा सकता है ।

जल संग्रहण क्षेत्रो में विशेषकर वन सम्पदा, प्राकृतिक आपदाऐ जल की आवश्यकता एवं उपलब्धता वर्षा चक्र कृषि क्रियाओ का विश्लेषण, फसल, बाजार, पशुपालन जनसंख्या के विभिन्न पक्ष आदि का समाकलित

अध्ययन करते हुए उपयुक्त विकास योजनाए तैयार करते हुए जनसहभागिता के साथ क्षेत्रीय विकास प्रारूप तैयार किया जा सकता है । ये सभी तथ्य एक दूसरे के पूरक एवं सह सबंधित माने गए है

इसके साथ ही किसी क्षेत्र विशेष में जल ग्रहण कार्यक्रमों से संलग्न विभिन्न क्रियान्वन एजेंसियों एवं लाभार्थियों को भी यह जानना आवश्यक है कि उनके द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यो की गुणात्मक एवं मात्रात्मक प्रगति क्या है ।

जल ग्रहण विकास कार्यक्रम जहाँ प्राथमिक संसाधनों के बेहतर उपयोग द्वारा कृषि विकास का एक समन्वित प्रयास है वही इसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया है की प्राकृतिक संतुलन पर किसी प्रकार का प्रतिकूल असर नहीं पड़े । जल ग्रहण विकास के कार्यक्रम की तकनीक स्थानीय समस्याओ पर अपना ध्यान केन्द्रित करती है साथ ही स्थानीय लोगो के सहयोग से परम्परागत ज्ञान का लाभ उठाते हुए इनके समाधान का प्रयास भी करती है ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Acharya S.S Singh -1990 water management Himanshu Publication, Udaipur
2. Jaspal and Sharma Arun – 1990 water management Himanshu Publication, Udaipur
3. Gurjar, R.K 1990 Geographical perspectives on Irrigation, Rawat Publication, Jaipur
4. Kathuria K.C 1978 Watershed Planning for optimum utilization of water Kurukshetra 26(21)
5. गुर्जर आर. के तथा जाट 1999 जलग्रहण विकास कार्यक्रम मरुधरा अकादमी, जयपुर
6. राजस्थान सुजस 2006 जल स्थापत्य, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, जयपुर
7. शर्मा बी0 एल0 2001 मृदा विज्ञान, वसुन्धरा प्रकाशन गोरखपुर
8. शर्मा डी0 एवं महर्षि हरि –1996 जल एवं जल प्रदूषण साहित्यागार, जयपुर

❖◆❖